



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 72) पटना, बृहस्पतिवार, 8 जनवरी 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

20 अक्टूबर 2014

सं0 9/आरोप (राज0) (नि0)—1—21/2012—4563—श्री देवेन्द्र पाठक, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध सरकारी नियमों का उल्लंघन एवं कदाचार के निमित्त पुनरीक्षित मूल्यांकन की मार्ग दर्शक पंजी को विलंब से पुनरीक्षित करने के कारण निर्धारित तिथि 18.01.2007 के पूर्व से लागू नहीं किया जाना, सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से छः माह पश्चात् पुनरीक्षित दर पर MVR लागू करने से स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क की क्षति का होना एवं विभागीय पत्रांक—2722 दिनांक 28.11.06 के द्वारा विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने तथा स्मार पत्र संख्या—207 दिनांक 17.01.07, 924 दिनांक 23.03.07, 1864 दिनांक 04.07.07, 1606 दिनांक 19.06.08 एवं 846 दिनांक 15.04.09 के द्वारा स्मारित करने के पश्चात् अत्यधिक विलंब से पत्रांक—148 दिनांक 12.05.09 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करना, सरकारी निर्देशों की जान बुझकर अवहेलना करने आदि के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित नियमावली 2007 के अंतर्गत प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या—519 दिनांक 22.02.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या—2398 दिनांक 09.08.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43बी0 में समपरिवर्तित किया गया।

2. अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा अपने पत्रांक—730 दिनांक 01.09.12 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप संख्या—1 एवं 3 को प्रमाणित नहीं माना गया एवं आरोप संख्या 02 के संबंध में उल्लेख किया गया कि मार्गदर्शक पंजी को बनाने में जो विलंब हुआ है, उसमें आरोपी की मात्र यह कमजोरी रही है कि वे बिहार प्रशासनिक सेवा के निबंधकों से पर्याप्त तालमेल स्थापित कर समय पर ऑकड़ा नहीं प्राप्त कर सके।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक—6367 दिनांक 12.12.2012 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। दिनांक 10.11.13 को श्री पाठक द्वारा अपने बचाव बयान में अपना बचाव बयान के स्थान पर मार्गदर्शक पंजी विलंब के समर्पित करने वाले अन्य जिला अवर निबंधकों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई जिसे किसी प्रकार से उचित नहीं माना गया। उक्त से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जान बुझकर मामलों को लंबित रखने का प्रयास किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री पाठक द्वारा दिये गये बचाव बयान के समीक्षोपरांत निष्कर्षित किया गया कि उनका बचाव बयान उन पर अधिरोपित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित

नहीं है। अतएव बिहार वित्त नियमावली के नियम 34 में निहित प्रावधान के आलोक में हुई राजस्व क्षति के लिये दोषी मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत उनकी सेवा पूर्ण संतोषजनक नहीं मानते हुए 10 (दस) प्रतिशत पेंशन से कटौती करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया। जिस पर बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के परंतुक (ग) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक-2170 दिनांक 26.05.14 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने पत्रांक-1319 दिनांक 03.09.14 द्वारा विचारोपरांत सूचित किया गया कि अरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नहीं है। आयोग में विभाग द्वारा पारित दंडादेश के पीछे दिये गये तर्कों की कोई समीक्षा नहीं की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पूर्ण पीठ की बैठक की कार्यवाही में विभाग द्वारा प्रस्तावित दण्ड को अनुपातिक नहीं बताए जाने के पीछे कोई यथेष्ट कारणों का उल्लेख नहीं रहने के कारण विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये परामर्श/अभिमत तथ्य परक नहीं माना गया है एवं अमान्य किये जाने योग्य पाया गया है।

5. अतएव पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री देवेन्द्र पाठक, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सारण की प्रशासनिक विफलता एवं कार्य के प्रति उदासीनता के कारण मार्गदर्शक पंजी को 22.07.06 के बजाय दिनांक 08.01.2007 यानि छः माह बाद लागू किये जाने कारण स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क के रूप में राज्य सरकार को हुई भारी वित्तीय क्षति के लिए उन्हें उत्तरदायी मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-139 बी0 एवं सी0 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 72-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>